ISSN: 3048-9423(Online)
Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS)
© NIJMS | Vol. 1 | Issue 3 | December-January 2025
Available online at: https://nijms.com/
DOI: https://doi.org/10.71126/nijms.v1i3.23

वर्तमान भारतीय ग्रामीण समाज में दलितों की शिक्षा एवं विकास पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ0 योगेश कुमार त्रिपाठी[1], डॉ0 कमल कश्यप[2], नितेश कुमार मौर्य[3]

[1]*असिस्टेंट प्रोफेसर (अतिथि), समाजशास्त्र विभाग, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (उ0प्र0)*

[2]*रामनगर, शंकरगंज, जौनपुर (उ0प्र0)*

[3]*शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग,राजकीय महिला महाविद्यालय, अहिरौला, आजमगढ़ (उ0प्र0)*

Email: *niteshsgm1997@gmail.com*

सार संक्षेप -

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों की 'शिक्षा एवं विकास' हमेशा से एक जटिल व चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है। ऐतिहासिक रूप से दलितों को समाज के अन्य हिस्सों से ''भेदभाव और असमानता'' का सामना करना पड़ा है, जो उनके 'शैक्षिक' व 'आर्थिक' विकास में महत्वपूर्ण बाधा है। इस शोध–पत्र का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में 'दलितों के शिक्षा' एवं 'विकास की समस्याओं' का विश्लेषण करना है तथा साथ ही उनके समाधान के लिए उपयुक्त उपायों को प्रस्तावित करना है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के लिए 'शिक्षा की गुणवत्ता', 'अवसर' एवं 'संसाधनों की कमी' सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही, 'सामाजिक भेदभाव', 'उच्च जातियों का हस्तक्षेप' एवं 'अभावग्रस्त परिवेश' भी इनके शिक्षा के मार्ग में अवरोधक बनते हैं। इसके बावजूद, सरकार ने 'आरक्षण', 'शिक्षा योजनाओं' व अन्य कल्याणकारी नीतियों के जरिए सुधार लाने की कोशिश की है। हालांकि, इन योजनाओं का सही माध्यम से क्रियान्वयन और दलित समुदायों तक इनका पहुंचना एक बड़ी समस्या है। निष्कर्ष यह है कि ''शिक्षा के क्षेत्र में दलितों को समान व सुलभ अवसर देने के लिए नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन, समाज में बदलाव और समानता की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है''।

मुख्य शब्द– *दलित, ग्रामीण शिक्षा, सामाजिक समानता, आरक्षण, विकास।*

परिचय–

भारत में, दलितों की 'शिक्षा' व 'विकास' एक गंभीर एवं जटिल मुद्दा है; विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में; दलित समुदाय को 'सामाजिक', 'आर्थिक' व 'शैक्षिक' अवसरों से वंचित रखा गया है। भारतीय समाज में ''जातिवाद' की गहरी जड़ें हैं, जिसके परिणामस्वरूप दलितों को हमेशा 'भेदभाव', 'छुआछूत' एवं 'उत्पीड़न' का सामना करना पड़ा है। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है; जहां इन समुदायों के पास संसाधनों, सुविधाओं एवं उचित अवसरों की भारी कमी है। शिक्षा, किसी भी समाज के विकास का मुख्य आधार मानी जाती है, यह 'दलित' समुदाय के लिए एक दूर का सपना बनी रहती है। सरकारी–निजी संस्थानों में दलितों के साथ भेदभाव व छुआछूत की घटनाएँ आम हैं, जिससे माध्यम से उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार, इन बच्चों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने या कक्षा में बैठने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त, 'सामाजिक भेदभाव' एवं 'जातिवाद' के कारण उनकी शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

'भारतीय संविधान' ने दलितों के लिए विशेष अधिकार व आरक्षण की व्यवस्था की है, किंतु इसका क्रियान्वयन एवं प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी एक चुनौती है। सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बावजूद, शिक्षा व विकास के क्षेत्र में दलितों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया है। जिसके चलते, दलितों को न केवल शिक्षा में, अपितु 'रोजगार' व 'सामाजिक मान्यता' में भी कठिनाइयों–असमानताओं का सामना करना पड़ता है। इस शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य ''दलितों की शिक्षा एवं विकास में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना तथा उनके समाधान के लिए सुलभ सुझाव साझा करना है''।

उद्देश्य –

1. भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों की शिक्षा में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।

2. दलितों की शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकारी योजनाओं का प्रभाव एवं उनके कार्यान्वयन का विश्लेषण करना।
3. दलितों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए संस्थागत एवं सामाजिक स्तर पर आवश्यक उपायों का सुझाव देना।
4. भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के लिए विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करना।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों की शिक्षा में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ–

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में, ''दलितों की शिक्षा'' एक अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु जटिल मुद्दा है। दलितों को समाज के निचले तबके के रूप में देखा गया है, जिस वजह से उन्हें विभिन्न 'सामाजिक', 'सांस्कृतिक', 'आर्थिक बाधाओं' व 'असमानताओं' का सामना करना पड़ा है। यह चुनौतियाँ उनकी शिक्षा में भी दिखाई देती हैं। सबसे पहली एवं प्रमुख चुनौती 'जातिवाद' व 'सामाजिक' भेदभाव है। भारतीय ग्रामीण समाज में 'जातिवाद' की गहरी जड़ें हैं व दलित बच्चों को अक्सर स्कूलों में 'पक्षपात' का सामना करना पड़ता है। कई बार 'शिक्षक' व 'अन्य छात्र' उन्हें सामाजिक अस्मिता के आधार पर कमतर समझते हैं। यह 'भेदभाव' व 'अलगाव' न केवल उनके मनोबल को गिराता है, वरन् 'शिक्षा की गुणवत्ता' पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है; कई बार तो 'दलित बच्चों' को स्कूलों में बैठने, पढ़ाई करने, या समान अवसरों व 'सुविधाओं' का लाभ उठाने से भी वंचित किया जाता है।

दूसरी प्रमुख चुनौती 'शिक्षा–संस्थानों की कमियाँ' हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की भारी कमी है एवं इसके साथ यदि स्कूल हैं भी, तो उनमें 'बुनियादी सुविधाओं का अभाव' व 'कमी है। कक्षाओं में पर्याप्त 'शिक्षकों की कमी', 'किताबों' एवं अन्य शैक्षिक सामग्री की अनुपलब्धता, और अपठनीय माहौल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रेरित करता है। इन सुविधाओं का अभाव व कमी दलित बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करने तथा उन्हें बेहतर अवसर देने में प्रमुख अवरोध का कारण बनता है। ''आर्थिक कारण'' भी एक बड़ी चुनौती है। दलित परिवारों की अधिकांश आय खेती या मजदूरी से आती है, जोकि अस्थिर व कम होती है। बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय कई बार उन्हें काम में लगा लिया जाता है, जिससे माध्यम से परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। इसके कारण, बच्चों को शिक्षा का सुलभ अवसर नहीं मिल पाता है; 'मनोवैज्ञानिक–सांस्कृतिक' बंधन भी दलित बच्चों की शिक्षा में एक प्रमुख चुनौती है। पारंपरिक रूप से, दलितों को समाज के उच्च वर्गों द्वारा नीचा माना जाता रहा है; इस मानसिकता का जोरदार असर बच्चों पर भी पड़ता है, जो अपनी शिक्षा को कम महत्व देते हैं। अंततः, 'सरकारी योजनाओं–नीतियों' का उचित क्रियान्वयन भी एक बड़ी समस्या है। बहुत सरकारी योजनाएँ, जैसे– आरक्षण, मुफ्त शिक्षा तथा छात्रवृत्तियाँ; अभी तक उपयुक्त तरीके से दलितों तक नहीं पहुँच पाई हैं। योजनाओं का स्थानीय स्तर पर सही क्रियान्वयन नहीं होने के कारण, वास्तविक लाभ दलित समुदाय तक नहीं पहुँचता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए केवल शिक्षा प्रणाली में सुधार की ही आवश्यकता नही है, अपितु समाज में भेदभाव–असमानता को जड़ से खत्म करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की भी अत्यधिक आवश्यकता है।

दलितों की शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकारी योजनाओं का प्रभाव और उनके कार्यान्वयन का विश्लेषण–

भारत सरकार ने दलितों की शिक्षा में सुधार के लिए अनेक योजनाओं–कार्यक्रमों को लागू किया है, जिनका मुख्य उद्देश्य, ''दलित समुदाय के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, व उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना है''। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं में ''सर्व शिक्षा अभियान'', ''मिड–डे–मील योजना'', ''भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएँ'' एवं ''आरक्षण नीति'' शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य, ''दलित बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर अधिक से अधिक ऊँचा करना एवं उनके लिए समान व सुलभ अवसर सुनिश्चित करना है''। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, सरकार ने ''दलित बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है''; इस योजना में, 6–14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें दलित छात्रों पर ध्यान दिया जाता है। ''मिड–डे–मील योजना'' के माध्यम से, बच्चों को स्कूल में भोजन दिया जाता है, जिसके चलते गरीबी के कारण शिक्षा में रुकावट न आए।

यद्यपि, इन योजनाओं का कार्यान्वयन उतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना अपेक्षित था। अनेक बार स्थानीय स्तर पर ''संसाधनों की कमी'', ''प्रशासनिक लापरवाही'' व ''अव्यवस्था के कारण'', योजनाओं का लाभ दलित बच्चों तक नहीं पहुँच पाता। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में; जहाँ स्कूलों की कमी व खराब बुनियादी ढाँचा है, योजनाओं का वास्तविक लाभ प्रभावित हुआ है। इस कारण, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सुधारने के लिए

उनकी निगरानी–प्रभावी क्रियान्वयन की अति आवश्यकता है, जिससे कि दलित बच्चों को उनकी शिक्षा में वास्तविक एवं दीर्घकालिक लाभ मिल सके।

दलितों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए ''संस्थागत–सामाजिक'' स्तर पर आवश्यक उपाय–

दलितों की शिक्षा में सुधार के लिए संस्थागत एवं सामाजिक स्तर पर बहुत आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों का उद्देश्य केवल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना ही नही है, वरन् समाज में 'समता', 'समावेशिता' व 'जागरूकता' को भी बढ़ाना है। संस्थागत उपाय, 1– शिक्षा के बुनियादी ढाँचे का सुधार, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करना जरूरी है। प्रत्येक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक, उपयुक्त कक्षाएँ, पुस्तकालय, शौचालय एवं अन्य सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षा का वातावरण गुणवत्तापूर्ण हो। 2– प्रशिक्षण एवं जागरूकता, शिक्षकों को दलित बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, जिससे कि वे भेदभाव से मुक्त, समावेशी एवं सहायक वातावरण बना सकें। इसके अलावा, शिक्षक व विद्यालय प्रशासन में जातिवाद के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। 3– प्रेरणा एवं मार्गदर्शन, संस्थानों में दलित बच्चों के लिए मार्गदर्शन तथा काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वे अपनी शिक्षा में आने वाली समस्याओं को हल कर सकें तथा अपने भविष्य के लिए बेहतर योजनाएँ बना सकें।

सामाजिक उपाय, 1– जातिवाद व भेदभाव के खिलाफ सामाजिक जागरूकता, समाज में जातिवाद के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इसके लिए सामाजिक संगठनों और समुदायों को मिलकर कार्य करना चाहिए; जिससे कि समाज में समता और समानता का संदेश फैलाया जा सके। 2– समाज में पारंपरिक सोच का बदलना, पारंपरिक जातिवादी सोच को चुनौती देना बेहद जरूरी है, जिससे कि दलित बच्चों को समान अवसर मिल सकें; इसके लिए सामाजिक आंदोलन एवं शिक्षात्मक कार्यशालाएँ आयोजित की जा सकती हैं। 3– पारिवारिक व सामुदायिक समर्थन, दलित समुदाय के परिवारों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए; साथ ही, स्थानीय समुदाय को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, जिससे कि वे शिक्षा को एक प्राथमिकता के रूप में मानें। इन उपायों के माध्यम से, हम केवल दलितों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ही नही कर सकते हैं, वरन् समाज में उनके लिए समान अवसर–सम्मान भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के लिए विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन–

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के लिए विकास की संभावनाएँ कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ऐतिहासिक एवं पारंपरिक जातिवादी सोच के रूप से दलित समुदाय को 'सामाजिक–आर्थिक–शैक्षिक' अवसरों से वंचित रखा गया है; फिर भी विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों एवं समाज में जागरूकता बढ़ने से इस समुदाय के विकास की संभावनाएँ बढ़ी हैं। बावजूद इसके, दलितों के लिए वास्तविक विकास की दिशा में अभी भी अनेक बाधाएँ हैं, जिन पर कार्य करना जरूरी है।

शैक्षिक क्षेत्र में विकास की संभावनाएँ, 'शिक्षा', किसी भी समाज के विकास की महत्वपूर्ण कुंजी है। भारत सरकार ने दलित समुदाय के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं, जैसे ''सर्व शिक्षा अभियान'' व ''मिड–डे–मील'', जोकि शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने में सहायक साबित हुई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से, दलित बच्चों के लिए स्कूलों तक पहुँच एवं शिक्षा का स्तर बढ़ाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं; हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की कमी–भेदभाव व अलगाव की समस्या अब भी बरकरार है, किंतु यदि शिक्षा का स्तर बेहतर किया जाता है, तो दलितों के लिए ''आत्मनिर्भरता'' एवं ''सामाजिक समावेश'' की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है।

आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र में विकास की संभावनाएँ, 'आर्थिक' दृष्टिकोण से देखा जाय तो ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के लिए विकास की संभावनाएँ प्रमुख रूप से 'कृषि', 'दस्तकारी', 'कारीगरी' एवं छोटे व्यवसायों पर निर्भर हैं। सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाएं, 'मनरेगा' (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) तथा 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना', ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने में मददगार रही हैं। इन योजनाओं के तहत दलितों को रोजगार एवं स्व–निर्भरता के अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से भी दलितों के विकास की संभावनाएँ बढ़ी हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा आरक्षण की व्यवस्था ने दलित समुदाय को 'शिक्षा', 'रोजगार' और 'राजनीति' में कुछ हद तक प्रतिनिधित्व दिलवाया है, किंतु, इन योजनाओं का पूरी तरह से लाभ मिलने के लिए 'कार्यान्वयन' और 'जागरूकता' में सुधार की आवश्यकता है।

संस्थागत एवं प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को साकार करने के लिए संस्थागत उचित सुधार भी जरूरी हैं। दलितों के लिए सरकारी योजनाओं का सही तरीके से 'क्रियान्वयन', 'प्रशासनिक दक्षता' तथा 'स्थानीय स्तर पर प्रशासन की भूमिका' अत्यंत महत्वपूर्ण है; यदि इन सुधारों को सही दिशा में लागू

किया जाय तो दलितों के लिए विकास की दिशा में काफी सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। कुल मिलाकर, भारत में दलितों के लिए विकास की संभावनाएँ उस दिशा में अधिक अग्रसर हैं जिसमें 'सामाजिक–शैक्षिक–आर्थिक समानता के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं; हालांकि, इसका वास्तविक लाभ तब मिलेगा जब योजनाओं का सही व उचितं तरीके से कार्यान्वयन एवं निगरानी हो।

निष्कर्ष–

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में 'दलितों की शिक्षा' व 'विकास की स्थिति' में सुधार की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं, किंतु समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं। दलित समुदाय को समाज के निचले तबके के रूप में देखा गया है, जिसके कारण उन्हें ऐतिहासिक रूप से 'भेदभाव–उत्पीड़न' का सामना करना पड़ा है। सरकारी योजनाओ–नीतियों के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के लिए 'शिक्षा', 'रोजगार' एवं 'सामाजिक समानता के अवसर' अभी भी सीमित हैं; हालांकि, 'मिड–डे–मील योजना', 'सर्व शिक्षा अभियान' एवं 'मनरेगा' जैसी योजनाओं ने दलितों के लिए कुछ सुलभ अवसर उत्पन्न किए हैं, किंतु इन योजनाओं का 'प्रभावी क्रियान्वयन' व 'संसाधनों की सही आपूर्ति' जरूरी है। 'जातिवाद', 'सामाजिक भेदभाव' व 'अलगाव' को खत्म करने के लिए एक 'सशक्त' एवं 'समावेशी' दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। 'समाज', 'सरकार' एवं विभिन्न संस्थाओं के सामूहिक प्रयास से दलितों के लिए बेहतर 'अवसर', 'समावेशिता' एवं 'सम्मान' सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि हम उचित दिशा में कार्य करें, निश्चित रूप तो भविष्य में दलित समुदाय के लिए 'शिक्षा', 'सामाजिक' एवं 'आर्थिक' विकास की उपलब्धियां व संभावनाएँ काफी हद तक उज्जवल हो सकती हैं।

संदर्भ सूची–

[1] घिवरिया, एवं मोहनलाल. (2008). आरक्षण से दलितों का जीवन सुधरा. *मूल प्रश्न*, 9–10.

[2] यादव, एवं राम शिवमूर्ति. (2008). सामाजिक न्याय हेतु ज़रूरी है आरक्षण. *मूल प्रश्न*, 22–28.

[3] रिनचिन, एवं महीन. (2010). शिक्षा, राजनीति और विचारधारा. संदर्भ, (69), 84–92.

[4] Jaffrelot, C. (2019). *Bhimrao Ambedkar: Ek Jeevani*. Rajkamal Prakashan.

[5] Kainth, G. S. (2006). A mission approach to Sarva Shiksha Abhiyan. *Economic and Political Weekly*, 3288-3291.

[6] Kurre, A. (2021). *Aanganabadi Mein Karyarat Shikshikaon Ka Samajashastrey Adhyayan*. Booksclinic Publishing.

[7] Tyagi, H. K., & Kumar, A. (2015). Sarva Shiksha Abhiyan--A Successful Scheme of Education in India. *Journal of Education and Practice*, *6*(28), 104-107.

[8] Sharma, Neha- (2020). Dalit Mukti ke sath Manav Mukti ki Agrahi Joothan. *IJRAR-International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, *7*(1), 901-907.

[9] Ward, M. (2011). Aid to education: the case of Sarva Shiksha Abhiyan in India and the role of development partners. *Journal of education policy*, *26*(4), 543-556.

Cite this Article:

डॉ0 योगेश कुमार त्रिपाठी, डॉ0 कमल कश्यप, नितेश कुमार मौर्य, "वर्तमान भारतीय ग्रामीण समाज में दलितों की शिक्षा एवं विकास पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण", Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS), ISSN: 3048-9423 (Online), Volume 1, Issue 3, pp. 59-62, December-January 2025.

Journal URL: https://nijms.com/

DOI: https://doi.org/10.71126/nijms.v1i3.23

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.